ईशा भट्टाचार्जी

बनाम

रघुनाथपुर नाफर की प्रबंधन समिति

अकादमी और अन्य

(सिविल अपील सं. 8183-8184/2013)

13 सितंबर, 2013।

[एनिल आर. डेव और दीपाक मिश्रा, जे. जे.]

देरीः/अवधि का बीत जाना

देर से दायर किए गए अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील-2449 दिनों की देरी को माफ करने की प्रार्थना-उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अनुमोदित-देरी को माफ करने के संबंध में सिद्धांत-निर्धारित अतिरिक्त दिशानिर्देश-आयोजित किए गएःसीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं-उनका उद्देश्य यह देखना है कि पक्ष विलम्बकारी रणनीति का सहारा न लें, बल्कि तुरंत अपना उपचार लें-प्रत्येक कानूनी उपाय को विधायी रूप से निर्धारित अवधि के लिए जीवित रखा जाना चाहिए-देरी को माफ करते हुए उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है-अपील।

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानः

विद्यालय की प्रबंध समिति-न्यायालय के आदेश का पालन न करना-अपील दायर करने में अत्यधिक देरी-आयोजितःजिन व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में नामित या शामिल किया जाता है या स्कूलों की प्रबंधन समितियों के सचिवों के रूप में चुना जाता है, उन्हें जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए और एक आकस्मिक दृष्टिकोण नहीं

अपनाना चाहिए-एक वैधानिक समिति अदालत द्वारा पारित आदेश के प्रति पूरी तरह से उदासीन नहीं रह सकती है। अपीलकर्ता, भाषा में सहायक शिक्षक समूह (बंगाली) ने उनकी नियुक्ति की मंजूरी और कुछ अन्य राहतों के लिए एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 25.2.2004 पर एक निर्देश जारी किया कि आवेदन विचाराधीनता रहने के दौरान, बंगाली में सहायक शिक्षक के रूप में याचिकाकर्ता की सेवाओं को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। एकल न्यायाधीश के समक्ष एक वचन दिया गया और तदनुसार अवमानना याचिका का निपटारा किया गया। हालाँकि, चूंकि अपीलकर्ता को अपने कर्तव्य में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने एक और अवमानना याचिका को प्राथमिकता दी।

उच्च न्यायालय के निर्देश के परिणामस्वरूप, उन्हें शामिल होने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्हें न तो दैनिक उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई, न ही कोई काम आवंटित किया गया और न ही उन्हें वेतन दिया गया। उन्होंने एक और अवमानना याचिका दायर की और 24.12.2010 पर एकल न्यायाधीश ने स्कूल के सचिव और प्रभारी शिक्षक की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया। इसके बाद प्रबंधन समिति और स्कूल के सचिव ने देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ एक अपील को प्राथमिकता दी, जिसमें दिनांकित 25.2.2004 के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई; और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने देरी को माफ कर दिया और रोक का एक अंतरिम आदेश भी पारित किया।

तत्काल अपीलों में, न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न थाःक्या उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ रिट याचिका में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 1 के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में 2449 दिनों की देरी को माफ करने के लिए आवेदन पर विचार करने में उचित थी।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. जहां तक विलंब की क्षमा के संबंध में, इस न्यायालय के निर्णयों में कानून के उच्चारण से, जिन सिद्धांतों को मोटे तौर पर निकाला जा सकता है, वे हैं (i) विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन पर विचार करते समय एक उदार, व्यावहारिक, न्यायाधीश उन्मुख, गैर-पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि अदालतों से अन्यायाधीश को वैध बनाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन वे अन्यायाधीश को दूर करने के लिए बाध्य हैं।

(ii) "पर्याप्त कारण" शब्द को इसकी उचित भावना, दर्शन और उद्देश्य के संबंध में इस तथ्य के संबंध में समझा जाना चाहिए कि यह शब्द मूल रूप से लोचदार है और तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उचित परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाना है।

(iii) पर्याप्त न्यायाधीश सर्वोपरि और महत्वपूर्ण होने के कारण तकनीकी विचारों पर अनुचित और अनावश्यक रूप से जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

(iv) देरी के जानबूझकर कारण के साथ कोई धारणा नहीं जोड़ी जा सकती है, लेकिन वकील या वादकारी की ओर से घोर लापरवाही पर ध्यान दें जाना चाहिए।

(v) विलंब की क्षमा की मांग करने वाले पक्ष के लिए प्रामाणिक ज्वार की कमी एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।

(vi) यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सख्त सबूतों का पालन सार्वजनिक न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करना चाहिए और सार्वजनिक शरारत का कारण नहीं बनना चाहिए क्योंकि अदालतों को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि अंतिम स्थिति में न्यायाधीश की कोई वास्तविक विफलता न हो।

(vii) उदार दृष्टिकोण की अवधारणा को तर्कसंगतता की अवधारणा को समाहित करना होगा और इसे पूरी तरह से मुक्त खेल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(viii) अत्यधिक विलम्ब और अल्पावधि या कुछ दिनों की विलम्ब के बीच अंतर है, क्योंकि पूर्वाग्रह का पूर्व सिद्धांत आकर्षित होता है जबकि बाद वाले की ओर यह आकर्षित नहीं हो सकता है।

इसके अलावा, पहला सख्त दृष्टिकोण का समर्थन करता है जबकि दूसरा एक उदार चित्रण का आह्वान करता है।

(ix) किसी पक्ष की निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित आचरण, व्यवहार और दृष्टिकोण प्रासंगिक कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह ऐसा है, क्योंकि मूल सिद्धांत यह है कि अदालतों को दोनों पक्षों के संबंध में न्यायाधीश के संतुलन के पैमाने को तौलना आवश्यक है और उक्त सिद्धांत को उदार दृष्टिकोण के नाम पर पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी जा सकती है।

(x) यदि प्रस्तुत स्पष्टीकरण मनगढ़ंत है या आवेदन में आग्रह किए गए आधार काल्पनिक हैं, तो अदालतों को सतर्क रहना चाहिए कि इस तरह के मुकदमे का सामना करने के लिए दूसरे पक्ष को अनावश्यक रूप से उजागर न करें।

(xi) यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोई भी सीमा कानून की तकनीकीताओं का सहारा लेकर धोखाधड़ी, गलत निरूपण या अंतर्वेशन से बच नहीं सकता है।

(xii) तथ्यों के पूरे सरगम की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और दृष्टिकोण न्यायिक विवेक के प्रतिमान पर आधारित होना चाहिए जो वस्तुनिष्ठ तर्क पर आधारित है न कि व्यक्तिगत धारणा पर।

(xiii) राज्य या एक सार्वजनिक निकाय या एक सामूहिक कारण का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई को कुछ स्वीकार्य अक्षांश दिया जाना चाहिए। [पैरा 15] [797-डी-एच; 798-ए-एच; 799-ए-सी]

कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और एक अन्य बनाम एमएसटी। कटीजी और अन्य 1987 (2) एस. सी. आर. 387 = 1987 (2) एस. सी. सी. 107, जी. रामगौड़ा, मेजर और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बैंगलोर 1988 (3) एस. सी. आर. 198 = 1988 (2) एस. सी. सी. 142; ओ. पी. कठपालिया बनाम लखमीर सिंह (मृत) और अन्य (1984) 4 एस. सी. सी. 66, नागालैंड राज्य बनाम लिपोक ए. ओ. और अन्य 2005 (3) एस. सी. आर. 108 = 2005 (3) एस. सी. सी. 752, न्यायालय ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वी. शांति मिश्रा 1976 (2) एस. सी. आर. 266 = 1975 (2) एस. सी. सी. 840, उत्तर हरियाणा राज्य बनाम चंद्र मणि 1996 (1) एस. सी. आर. 1060 = 1996 (3) एस. सी. सी. 132 और विशेष तहसीलदार, भूमि अधिग्रहण बनाम के. वी. आयसुम 1996 (3) का उल्लेख करने के बाद। एस. सी. आर. 848 = 1996 (10) एस. सी. सी. 634, ओरिएंटल अरोमा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गुजरात औद्योगिक विकास निगम और एक अन्य 2010 (2) एस. सी. आर. 1172 = 2010 (5) एस. सी. सी. 459, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लुधियाना बनाम। उजागर सिंह और अन्य 2010 (7) एस. सी. आर. 376 = 2010 (6) एस. सी. सी. 786; बा/वांट सिंह (मृत) बनाम जगदीश सिंह और अन्य 2010 (8) एस. सी. आर. 597 = 2010 (8) एस. सी. सी. 685 भारत संघ बनाम राम चरण 1964 एस. सी. आर. 467 = ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 215, पी. के. रामचंद्रन बनाम केरा राज्य/एक 1997 (4) पूरक। एस. सी. आर. 204 = 1997 (7) एस. सी. सी. 556; और कटारी सूर्यनारायण बनाम कोप्पिसेट्टी सुब्बा राव 2009 (5) एस. सी. आर. 672 = 2009 (11) एस. सी. सी. 183; मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम (2012) 5 एस. सी. सी. 157, वेदाबाई बनाम शांताराम बाबूराव पाटिल 2001 (3) एस. सी. आर. 1053 = 2001 (9) एस. सी. सी. 106; बी. माधुरी गौड़ बनाम बी. दामोदर रेड्डी 2012 (12) एस. सी. सी. 693-संदर्भित।

1.2. वर्तमान परिदृश्य ध्यान दें में रखते हुए निम्नलिखित दिशानिर्देश भी जोड़े जा सकते हैं

(क) विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन का मसौदा सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए न कि आधे जोखिम वाले तरीके से यह धारणा रखते हुए कि न्यायाधीशालयों को इस सिद्धांत के आधार पर विलम्ब को माफ करने की आवश्यकता है कि गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना न्यायाधीश वितरण प्रणाली के लिए मौलिक है।

(ख) विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन को व्यक्तिगत दर्शन के आधार पर नियमित तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए जो मूल रूप से व्यक्तिपरक है।

(ग) यद्यपि न्यायिक विवेकाधिकार की अवधारणा के संबंध में कोई सटीक सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी न्यायनिर्णायक प्रणाली की स्थिरता और सामूहिकता प्राप्त करने के लिए एक सचेत प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि यही अंतिम संस्थागत आदर्श वाक्य है।

(घ) विलंब को एक गैर-गंभीर मामले के रूप में समझने की बढ़ती प्रवृत्ति और इसलिए, अभावपूर्ण प्रवृत्ति को गैर-चुनौतीपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, निश्चित रूप से, कानूनी मापदंडों के भीतर नियंत्रित करने की आवश्यकता है। [पैरा 16] [799-सी-एच]

1.3. तत्काल मामले में, उच्च न्यायाधीशालय की खण्ड पीठ ने कुछ तथ्यों पर विचार नहीं करके खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है, अर्थात् (ए) कि रिट याचिका का नोटिस पूर्ववर्ती प्रबंधन समिति को दिया गया था; (बी) कि पूर्ववर्ती समिति रिट अदालत में पेश हुई थी और कार्यवाही और आदेश से अवगत थी; (सी) कि स्कूलों के जिला निरीक्षक ने एकल न्यायाधीशाधीश के आदेश का पालन करने के लिए प्रबंधन

समिति को सूचित किया था; (डी) कि पूर्ववर्ती प्रबंधन समिति ने आदेश का पालन करने के लिए एकल न्यायाधीशाधीश के समक्ष कार्य किया था; (ई) कि नई प्रबंधन समिति ने पूर्ववर्ती प्रबंधन समिति से कार्यभार संभाला था; (एफ) शपथ पत्र में कुछ भी संकेत नहीं दिया गया है कि किस परिस्थिति में नई प्रबंधन समिति ने कार्यभार संभालने के बावजूद, कार्यभार नहीं संभाला था। [पैरा 21) [802-जी-एच; 803-ए-ई]

1.4. ज्ञान की कमी की दलील, तत्काल मामले में, वास्तव में प्रामाणिकता का अभाव है। उच्च न्यायाधीशालय की खण्ड पीठ न्यायाधीशिक विवेकाधिकार के प्रयोग की अवधारणा के प्रति खुद को जीवित रखने में विफल रही है जो तर्क और न्यायाधीश के नियमों द्वारा शासित है। सीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं। वे यह देखने के लिए हैं कि पक्ष विलम्बकारी रणनीति का सहारा न लें, बल्कि तुरंत अपना उपचार लें। प्रत्येक कानूनी उपाय को विधायी रूप से निर्धारित अवधि के लिए जीवित रखा जाना चाहिए। [पैरा 22) [804-ए, डी-ई]

बालकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति 1998 (1) पूरक। एस. सी. आर. 403 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 3222-पर निर्भर।

1.5. जिन व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में नामित या शामिल किया जाता है या स्कूलों की प्रबंधन समितियों के सचिवों के रूप में चुना जाता है, उन्हें जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए और एक आकस्मिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। यह एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है और जो कोई भी इस तरह की जिम्मेदारी लेने का इच्छुक है, उसे समय देना होगा और उचित सावधानी और आवश्यक सावधानी के साथ कार्य करना होगा। एक सांविधिक समिति न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रति पूरी तरह से उदासीन नहीं रह सकती है। [पैरा 22) [803-ई-जी]

1.6. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा विलंब को माफ करते हुए पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है। रिट याचिका का शीघ्रता से निपटारा किया जाएगा। [पैरा 23) [804-एफ]

मामला कानून संदर्भः

1987 (2) एससीआर 387	संदर्भित किया गया है	पैरा 6
1988 (3) एससीआर 198	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
(1984) 4 एस. सी. सी. 66	निर्दिष्ट है	पैरा 8 ए
2005 (3) एससीआर 108	संदर्भित किया गया है	पैरा 9
1976 (2) एससीआर 266	संदर्भित किया गया है	पैरा 9
1998 (1) पूरक एस. सी. आर. 403	पर निर्भर	पैरा 9
1996 (1) एस. सी. आर. 1060	संदर्भित	पैरा 9
1996 (3) पूरक एस. सी. आर. 848	संदर्भित	पैरा 9
2010 (2) एससीआर 1172	संदर्भित किया गया है	पैरा 10
2010 (7) एससीआर 376	संदर्भित किया गया है	पैरा 11
2010 (8) एससीआर 597	संदर्भित किया गया है	पैरा 12
1964 एससीआर 467	संदर्भित किया गया है	पैरा 12
1997 (4) पूरक। एस. सी. आर. 204	संदर्भित	पैरा 12
2009 (5) एस. सी. आर. 672	संदर्भित	पैरा 12
सी 2012 5 सेकंड 157	संदर्भित किया गया है	पैरा 13
2001 (3) एससीआर 1053	संदर्भित किया गया है	पैरा 13

2012 (12) सेक 693 संदर्भित किया गया है पैरा 14

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णयः दीवानी याचिका सं 8183-8184/2013

कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2011 के ए. एस. टी. 13 में 2011 के ए. एस. टी. ए. 10 के साथ 2011 के सी. ए. एन. संख्या 365 में दिनांकित 21.02.2011 के निर्णय और आदेश से।

कूना चटर्जी, अपीलकर्ता अनीप सचथे के लिए मैत्रेयी बनर्जी, प्रतिवादीओं के लिए सारद कुमार सिंघानिया।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, जे. द्वारा दिया गया था।

1. दोनों विशेष अवकाश अनुदत्त याचिकाओं में अवकाश अनुदत्त दी गई।

2. हम इन अपीलों में विशेष अनुमति द्वारा जिस एकल प्रश्न को संबोधित करने का इरादा रखते हैं, वह यह है कि क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ 2011 के सी. ए. एन. संख्या 365 पर विचार करने में उचित है कि उसने 2004 के डब्ल्यू. पी. संख्या 6124 (डब्ल्यू) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ 2011 की संख्या 10 में 2449 दिनों की देरी को माफ कर दिया। यह भी ध्यान दें योग्य है कि 2011 की ए. एस. टी. सं. 13 में 2011 की सं. 10 में खण्ड पीठ ने 2004 की ए. एस. टी. सं. 346 के संबंध में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। कहने की जरूरत नहीं है कि उक्त आदेश परिणामी है क्योंकि पूरी बात देरी की माफी से संबंधित मुद्दे पर निर्भर करेगी।

3. अनावश्यक विवरणों के बिना, वर्तमान अपीलों के निपटारे के उद्देश्य से जो तथ्य बताए जाने आवश्यक हैं, वे यह हैं कि अपीलकर्ता, भाषा समूह (बंगाली) में एक सहायक शिक्षक, ने अपनी नियुक्ति की मंजूरी और कुछ अन्य राहतों के लिए एक रिट याचिका को प्राथमिकता देकर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के

अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। आई. डी. 1 पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर ध्यान देते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ध्यान देंिस के बावजूद संबंधित प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था, एक निर्देश जारी किया कि आवेदन विचाराधीनता रहने के दौरान हावड़ा जिले के अभयनगर में रघुनाथपुर नफ़र अकादमी (एच. एस.) में बंगाली में सहायक शिक्षक के रूप में याचिकाकर्ता की सेवाओं को अगले आदेश तक बाधित नहीं किया जाएगा। चूंकि उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता ने 2004 का सी पी ए एन संख्या 1016 के रूप में अवमानना आवेदन दायर किया। यह ध्यान दिया जाए कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने स्कूल के अधिकारियों को आदेश के बारे में सूचित किया लेकिन उक्त संचार पर ध्यान नहीं दिया गया। 24.1.2006 पर स्कूलों के जिला निरीक्षक (एस. ई.), हावड़ा ने उक्त स्कूल अधिकारियों को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया। उक्त निर्देश के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक वचन दिया गया था और उस आधार पर 2004 की सं. 1016 का निपटारा किया गया था। जैसे-जैसे तथ्यात्मक मैट्रिक्स आगे बढ़ेगा, 21.11.2009 पर स्कूल की पूर्ववर्ती प्रबंधन समिति के स्थान पर एक नई प्रबंधन समिति का गठन किया गया और बी अपीलकर्ता को अपने कर्तव्य में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। विवश होने के कारण, उन्होंने एक और अवमानना याचिका नं. 2010 का सं. 1506, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने पूर्व आदेश का उल्लेख किया और निर्देश दिया कि जिला विद्यालय निरीक्षक (एस. ई.) आदेश का उचित अनुपालन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, एक निर्देश जारी किया गया था कि संबंधित पुलिस प्राधिकरण को यह देखना चाहिए कि संबंधित स्कूल के सचिव और प्रभारी शिक्षक याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों में शामिल होने की अनुमति देने के आदेश को

लागू करें। उक्त आदेश पारित होने के बाद, यहाँ अपीलकर्ता 14.6.2010 से सहायक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों में शामिल हो गई। हालाँकि अपीलकर्ता को शामिल होने की अनुमति दी गई थी, फिर भी उसे न तो दैनिक उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई, न ही कोई काम आवंटित किया गया और न ही उसे वेतन दिया गया। प्रेरित होकर, उन्होंने अवमानना के लिए एक आवेदन दायर किया, 2010 का सी पी ए एन संख्या 1506, और 24.12.2010 पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्कूल के सचिव और प्रभारी शिक्षक की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए निर्देश दिया। इस मोड़ पर, प्रबंधन समिति और स्कूल के सचिव ने देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ एक अपील को प्राथमिकता दी। उक्त आवेदन का अपीलकर्ता ने एक शपथ पत्र दाखिल करके गंभीरता से विरोध किया और अंततः, विवादित आदेश द्वारा खण्ड पीठ ने देरी को माफ कर दिया। यह ध्यान दिया जाए कि खण्ड पीठ ने स्थगन का एक अंतरिम आदेश भी पारित किया है। विशेष अवकाश द्वारा इन अपीलों में उक्त आदेश हमले का विषय हैं।

4. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कुणाल चटर्जी, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनीप सचथे और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री सारद कुमार सिंघानिया को सुना है।

5. इससे पहले कि हम तथ्यात्मक परिदृश्य और विलंब को क्षमा करने वाले आदेश की रक्षात्मकता में तल्लीन हों, ऐसा प्रतीत होता है कि विलंब को क्षमा करने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय अदालत के दायित्व और इस तरह की भारी देरी को क्षमा करने के आधारों पर विचार करते समय अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को बताना है।

6. कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और अन्य बनाम एम. एस. टी. काटीजी और अन्य 1, दो-न्यायाधीशाधीशों की पीठ ने कहा कि विधायिका ने 1963 के भारतीय सीमा अधिनियम की खंड 5 को लागू आदेशके देरी को माफ आदेशने की शक्ति प्रदान की है ताकि अदालतें गुण-दोष के आधार पर मामलों का निपटारा आदेशके पक्षों के साथ पर्याप्त न्यायाधीश आदेश सकें। विधायिका द्वारा प्रयुक्त "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति अदालतों को कानून को सार्थक तरीके से लागू करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से लोचदार है जो न्यायाधीश के उद्देश्यों को कम करता है, क्योंकि यह अदालतों की संस्था के अस्तित्व के लिए जीवन-उद्देश्य है। विद्वान न्यायाधीशाधीशों ने देरी की माफी के लिए आवेदनों पर विचार करते समय एक उदार दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया क्योंकि आम तौर पर एक वादकारी को देर से अपील दायर करने से लाभ नहीं होता है और देरी को माफ करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप एक सराहनीय मामला बहुत हद तक बाहर फेंक दिया जा सकता है और न्यायाधीश का कारण विफल हो सकता है। इस बात पर जोर दिया गया कि एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि इस मामले को तर्कसंगत सामान्य समझ व्यावहारिक तरीके से निपटाया जाना चाहिए और तकनीकी विचारों पर पर्याप्त न्यायाधीश के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भी फैसला दिया गया कि ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि देरी जानबूझकर या दोषपूर्ण लापरवाही के कारण की गई है और अदालतों से तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की अपेक्षा नहीं की जाती है क्योंकि अन्याय को दूर करना अदालत का कर्तव्य है। उक्त मामले में खण्ड पीठ ने कहा कि जो राज्य समुदाय के सामूहिक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है, वह वादी-गैर-वांछनीय स्थिति का हकदार नहीं है और अदालतों को "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति की व्याख्या के दौरान प्रावधान की भावना और दर्शन के साथ सूचित करने की आवश्यकता है।

7. जी. रामगौड़ा, मेजर और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बैंगलोर, वेंकटचलैया, जे. (जैसा कि उनका लॉर्डशिप तब था) ने अदालत की ओर से बोलते हुए इस प्रकार राय दी हैः-

> "अपील दायर करने में देरी को माफ करने के मामले में अदालतों के विवेकाधिकार के क्षेत्र की रूपरेखा इस अदालत के कई निर्णयों में निर्धारित की गई है। देखिएः
>
> राम/अल, मोटिला/और च होटल अल बनाम रीवा कोलफील्ड लिमिटेड 3; शकुंतला देवी जैन बनाम कुंतल कुमारी; कॉनकॉर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वी. निर्मला देवी 5; लाला माता दिन बनाम ए. नारायणन 6; कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण बनाम कटीजी आदि। यह सच है कि कोई भी सामान्य सिद्धांत पक्ष को उसकी सलाह की सभी गलतियों से नहीं बचाता है। यदि पक्ष या उसके वकील की ओर से लापरवाही, जानबूझकर या घोर निष्क्रियता या प्रामाणिक रूप से कोई कारण है तो कोई कारण नहीं है कि विरोधी पक्ष को समय-बाधित अपील के लिए उजागर किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले को उसके अपने विशेष तथ्यों की विशिष्टताओं पर विचार करना होगा। हालांकि, खंड 5 में 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति को एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए ताकि पर्याप्त न्यायाधीश को आगे बढ़ाया जा सके और आम तौर पर अपीलों को प्राथमिकता देने में देरी को न्यायाधीश के हित में माफ किया जाना आवश्यक है, जहां कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या विलंब की माफी की मांग करने वाले पक्ष के लिए प्रामाणिक रूप से आरोप लगाया जा सकता है।

8. ओ. पी. कठपालिया बनाम लखमीर सिंह (मृत) और अन्य 7 मामले में, अदालत एक तथ्य-स्थिति पर विचार कर रही थी, जिसमें पहली बार अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश एक अंतर्वेष्टित आदेश था और यह पता नहीं चल सका था कि आदेश कब दिया गया था। उक्त आदेश जिले के समक्ष अपील के अधीन था।

1. (1984) 4 सेक 66।

2. (1988) 2 धारा 142।

3. (1962) 2 एससीआर 762।

4. (1969) 1 एससीआर 1006।

5. (1979) 3 एससीआर 694।

6. (1970) 2 एससीआर 90।

एक न्यायाधीश जिसने देरी को माफ करने से इनकार कर दिया और उक्त दृष्टिकोण से उच्च न्यायालय ने सहमति व्यक्त की। न्यायाधीशालय ने तथ्यों का जायजा लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यदि इस तरह के अंतर्वेष्टित आदेश को कायम रहने दिया जाता है, तो न्यायाधीश की विफलता होगी और तदनुसार, इसमें आक्षेपित आदेशों को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि जिला न्यायाधीशाधीश के समक्ष अपील गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के योग्य है।

9. नागालैंड राज्य बनाम लिपोक एओ और अन्य 8 के मामले में, न्यायाधीशालय ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वी. शांति मिश्रा 9, एन. बालकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति, हरियाणा राज्य बनाम चंद्र मणि 1 और विशेष तहसीलदार, भूमि अधिग्रहण बनाम के. वी. आयसुममा 12 का उल्लेख करने के बाद कहा कि सबूत के सख्त मानक को अपनाना कभी-कभी सार्वजनिक न्यायाधीश की रक्षा करने में विफल रहता है और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शरारत हो सकती है।

10. इस संदर्भ में, हम ओरिएंटल अरोमा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गुजरात औद्योगिक विकास निगम और अन्य 13 में प्राधिकरण को लाभ के साथ संदर्भित कर सकते हैं, जहां इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि सीमा का कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है। विधायिका दलों के अधिकारों को नष्ट करने के उद्देश्य के साथ सीमा निर्धारित नहीं करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि वे विलंबकारी रणनीति का सहारा न लें और बिना देरी के उपचार की तलाश करें। विचार यह है कि प्रत्येक कानूनी उपाय को विधायिका द्वारा निर्धारित अवधि के लिए जीवित रखा जाना चाहिए। इसे अलग तरह से रखने के लिए, सीमा का कानून एक ऐसी अवधि निर्धारित करता है जिसके भीतर कानूनी चोट के निवारण के लिए कानूनी उपचार का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही, अदालतों को देरी को माफ करने की शक्ति प्रदान की जाती है, यदि निर्धारित समय के भीतर उपचार का लाभ नहीं उठाने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया जाता है। इसके बाद, विद्वान न्यायाधीशों ने आगे कहा कि इस न्यायालय ने न्यायसंगत रूप से

8. (2005) 3 धारा 752।

9. (1975) 2 सेक 840।

10. ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 3222

11. (1996) 3 धारा 132।

12. (1996) 10 धारा 634।

13. 2010 5 धारा 459।

अल्प अवधिक विलम्बकेँ माफ करबा लेल उदार दृष्टिकोण अपनयबाक वकालत कयलनि आ एकटा कठोर दृष्टिकोण अपनयबाक वकालत कयलनि जतऽ विलम्ब अत्यधिक होयत छैक।

11. इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लुधियाना बनाम उजागर सिंह और अन्य 14 में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विलंब की माफी के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय निष्कर्ष पर आने के लिए कोई स्ट्रेटजैकेट सूत्र निर्धारित नहीं किया गया है यदि पर्याप्त और अच्छा आधार बनाया गया है या नहीं। इसमें आगे कहा गया है कि प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों और उन परिस्थितियों से तौलना होगा जिनमें पक्ष कार्य करता है और व्यवहार करता है।

12. बा/वांट सिंह (मृत) बनाम जगदीश सिंह और अन्य 15 में बताए गए सिद्धांत का संदर्भ काफी फलदायी होगा। उक्त मामले में न्यायालय ने भारत संघ बनाम राम चरण 16, पी. के. रामचंद्रन बनाम केरल राज्य 17 और कटारी सूर्यनारायण बनाम कोप्पिसेट्टी सुब्बा राव 18 के फैसलों का उल्लेख किया और इस प्रकार कहाः-

> "25. हम कह सकते हैं कि भले ही "पर्याप्त कारण" शब्द को उदार निर्माण प्राप्त करना हो, लेकिन यह पूरी तरह से संबंधित पक्ष के उचित समय और उचित आचरण की अवधारणा के भीतर आना चाहिए। उदार निर्माण शुरू करने का उद्देश्य आम तौर पर "तर्कसंगतता" की अवधारणा को पेश करना है क्योंकि इसे इसके सामान्य अर्थ में समझा जाता है।
>
> 26. परिसीमा का कानून एक मूल कानून है और किसी पक्ष के अधिकार और दायित्व पर इसके निश्चित परिणाम होते हैं। इन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए और किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। एक बार जब एक पक्ष के पक्ष में एक मूल्यवान अधिकार अर्जित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दूसरा पक्ष पर्याप्त कारण

और अपने स्वयं के आचरण को दिखाकर देरी की व्याख्या करने में विफल रहता है, तो केवल आवेदक से पूछने पर उस अधिकार को छीनना अनुचित होगा, विशेष रूप से जब देरी सीधे उस पक्ष की लापरवाही, चूक या निष्क्रियता का परिणाम है। दोनों पक्षों के साथ समान रूप से न्यायाधीश किया जाना चाहिए। तभी न्यायाधीश के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई पक्ष अपने अधिकारों और उपचारों को लागू करने में पूरी तरह से लापरवाही करता रहा है, तो दूसरे पक्ष को उस मूल्यवान अधिकार से वंचित करना भी उतना ही अनुचित होगा जो उसके सतर्कतापूर्वक कार्य करने के परिणामस्वरूप उसे कानून में प्राप्त हुआ है।"

13. हाल ही में मनीबेन देवराज शाह बनाम बृहन्मुंबत नगर निगम 19 में, विद्वान न्यायाधीशों ने वेदाबाई बनाम शांताराम बाबूराव पति में उस घोषणा का उल्लेख किया जिसमें यह राय दी गई है कि एक ऐसे मामले के बीच अंतर किया जाना चाहिए जहां देरी अत्यधिक है और एक ऐसा मामला जहां देरी कुछ दिनों की है और जबकि पहले वाले मामले में दूसरे पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह का विचार एक प्रासंगिक कारक होगा, बाद वाले मामले में ऐसा कोई विचार नहीं होता है। इसके बाद, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार फैसला सुनायाः-

"23. जिस बात पर जोर देने की आवश्यकता है वह यह है कि भले ही सीमा अधिनियम की खंड 5 और इसी तरह के अन्य कानूनों के तहत शक्ति के प्रयोग में एक उदार और न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, लेकिन अदालतें न तो इस तथ्य से अनजान हो सकती हैं कि सफल वादकारी ने चुनौती के तहत निर्णय

के आधार पर कुछ अधिकार हासिल किए हैं और मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों में लागत के अलावा बहुत समय लगता है।

24. किसी दिए गए मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति को क्या रंग मिलेगा, यह काफी हद तक स्पष्टीकरण की प्रामाणिक प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि अदालत को लगता है कि आवेदक की ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई है और देरी के लिए दिखाए गए कारण में ईमानदारी की कमी नहीं है, तो वह देरी को माफ कर सकती है। यदि दूसरी ओर, आवेदक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण मनगढ़ंत पाया जाता है या वह अपने कारण पर मुकदमा चलाने में पूरी तरह से लापरवाही करता है, तो देरी को माफ नहीं करना विवेक का एक वैध अभ्यास होगा।

अंततः, पीठ ने विलंब की क्षमा के लिए आवेदन और अभिलेख पर शपथ पत्र के अवलोकन पर यह अभिनिर्धारित किया कि कुछ आवश्यक तथ्य स्पष्ट रूप से मौन थे और तदनुसार, उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया, जिसने सात साल से अधिक की देरी को माफ कर दिया था।"

14. बी. माधुरी गौड़ बनाम बी. दामोदर रेड्डी 21 में, न्यायालय ने पहले के फैसलों का उल्लेख करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया, जिन्होंने 1236 दिनों की देरी को माफ कर दिया था क्योंकि देरी की माफी के लिए आवेदन में दिया गया स्पष्टीकरण आत्यन्तिक रूप काल्पनिक था।

15. उपरोक्त अधिकारियों से जिन सिद्धांतों को व्यापक रूप से निकाला जा सकता है, वे हैं:

(i) विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन पर विचार करते समय एक उदार, व्यावहारिक, न्याय-उन्मुख, गैर-पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि अदालतों से अन्याय को वैध बनाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन वे अन्याय को दूर करने के लिए बाध्य हैं।

(ii) "पर्याप्त कारण" शब्दों को उनकी उचित भावना, दर्शन और उद्देश्य में इस तथ्य के संबंध में समझा जाना चाहिए कि ये शब्द मूल रूप से लोचदार हैं और तथ्य-स्थिति प्राप्त करने के लिए उचित परिप्रेक्ष्य में लागू किए जाने चाहिए।

(iii) पर्याप्त न्यायाधीश सर्वोपरि और महत्वपूर्ण होने के कारण तकनीकी विचारों पर अनुचित और अनावश्यक रूप से जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

(iv) देरी के जानबूझकर कारण के साथ कोई धारणा नहीं जोड़ी जा सकती है, लेकिन वकील या वादकारी की ओर से घोर लापरवाही पर ध्यान दें जाना चाहिए।

(v) विलंब की क्षमा की मांग करने वाले पक्ष के लिए प्रामाणिक विश्वास की कमी एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।

(vi) यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सख्त सबूतों का पालन सार्वजनिक न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करना चाहिए और सार्वजनिक गड़बड़ी का कारण नहीं बनना चाहिए क्योंकि अदालतों को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि अंतिम रूप से न्यायाधीश की कोई वास्तविक विफलता न हो।

(vii) उदार दृष्टिकोण की अवधारणा को तर्कसंगतता की अवधारणा को समाहित करना होगा और इसे पूरी तरह से मुक्त खेल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(viii) अत्यधिक विलम्ब और अल्पावधि या कुछ दिनों की विलम्ब के बीच अंतर है, क्योंकि पूर्वाग्रह का पूर्व सिद्धांत आकर्षित होता है जबकि बाद वाले की ओर यह

आकर्षित नहीं हो सकता है। इसके अलावा, पहला सख्त दृष्टिकोण का समर्थन करता है जबकि दूसरा एक उदार चित्रण का आह्वान करता है।

(ix) किसी पक्ष की निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित आचरण, व्यवहार और दृष्टिकोण प्रासंगिक कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह इस तरह है कि

मौलिक सिद्धांत यह है कि अदालतों को दोनों पक्षों के संबंध में न्यायाधीश के संतुलन के पैमाने को तौलना आवश्यक है और उक्त सिद्धांत को नहीं माना जा सकता है

उदार दृष्टिकोण के नाम पर कुल जाना जाता है।

(x) यदि प्रस्तुत स्पष्टीकरण मनगढ़ंत है या आवेदन में आग्रह किए गए आधार काल्पनिक हैं, तो अदालतों को सतर्क रहना चाहिए कि इस तरह के मुकदमे का सामना करने के लिए दूसरे पक्ष को अनावश्यक रूप से उजागर न करें।

(xi) यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोई भी सीमा कानून की तकनीकीताओं का सहारा लेकर धोखाधड़ी, गलत निरूपण या अंतर्वेशन से बच नहीं सकता है।

(xii) तथ्यों के पूरे सरगम की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और दृष्टिकोण न्यायिक विवेक के प्रतिमान पर आधारित होना चाहिए जो वस्तुनिष्ठ तर्क पर आधारित है न कि व्यक्तिगत धारणा पर।

(xiii) राज्य या एक सार्वजनिक निकाय या एक सामूहिक कारण का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई को कुछ स्वीकार्य अक्षांश दिया जाना चाहिए।

16. उपरोक्त सिद्धांतों में हम वर्तमान परिदृश्य ध्यान दें में रखते हुए कुछ और दिशानिर्देश जोड़ सकते हैं। वे इस प्रकार हैं-

(क) विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन का मसौदा सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए न कि आधे जोखिम वाले तरीके से यह धारणा रखते हुए कि न्यायाधीशालयों को इस सिद्धांत के आधार पर विलम्ब को माफ करने की आवश्यकता है कि गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना न्यायाधीश वितरण प्रणाली के लिए मौलिक है।

(ख) विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन को व्यक्तिगत दर्शन के आधार पर नियमित तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए जो मूल रूप से व्यक्तिपरक है।

(ग) यद्यपि न्यायिक विवेकाधिकार की अवधारणा के संबंध में कोई सटीक सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी न्यायनिर्णायक प्रणाली की स्थिरता और सामूहिकता प्राप्त करने के लिए एक सचेत प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि यही अंतिम संस्थागत आदर्श वाक्य है।

(घ) विलंब को एक गैर-गंभीर मामले के रूप में समझने की बढ़ती प्रवृत्ति और इसलिए, अभावपूर्ण प्रवृत्ति को गैर-चुनौतीपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, निश्चित रूप से, कानूनी मापदंडों के भीतर नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

17. वर्तमान में विलंब की क्षमा के लिए आवेदन में किए गए दावों और उसी के विरोध में अलग-अलग दावे। यहां यह कहा जा सकता है कि खण्ड पीठ ने देरी की माफी के आवेदन पर विचार करते हुए एक शिक्षक की नियुक्ति और अनुमोदन के मामले में अंतरिम आदेश की कानूनी वैधता को भी स्वीकार किया है और देरी को माफ कर दिया है। यह समझने के लिए सोलोमन के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि देरी बहुत बड़ी थी। विलंब की क्षमा के लिए आवेदन में उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने उन परिस्थितियों के बारे में कहा था जिनमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित किया गया था, पूर्व की अवमानना याचिका में आदेश और

अवमानना के लिए दूसरी याचिका, प्रतिवादी कर्मचारी के पद पर बने रहने के अधिकार को समाप्त करना और उसके बाद देरी की क्षमा के लिए आधार बताने के लिए आगे बढ़ना। हम इन आधारों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:

> "14. रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि विवादित आदेश को तत्कालीन प्रबंध समिति को सूचित किया गया था, जिसमें विचाराधीन प्रधान शिक्षक भी शामिल थे और उक्त तथ्य नवनिर्वाचित प्रबंधन समिति को पूरी तरह से अज्ञात है क्योंकि वे 20.9.2009 पर चुने गए हैं और उन्हें 21.11.09 पर प्रभार सौंपा गया है और प्रभारी शिक्षक को जिसे 1.3.10 पर प्रभार सौंपा गया है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना उचित है कि नोटिस और अवमानना आवेदन प्राप्त करने के बाद आवेदकों ने एल. डी. को सौंपा। उचित कदम उठाने के लिए अधिवक्ता और उन्हें मामले का बचाव करने की सलाह दी गई है, लेकिन गलत संचार के कारण आवेदक ने यहां फिर से श्री बनिक, एल. डी. से संक्षिप्त जानकारी सौंपी। श्री बैद्य के लिए अधिवक्ता, एल. डी. अधिवक्ता। उक्त कागजात प्राप्त करने के बाद और सभी अभिलेखों को पढ़ने के बाद उन्होंने अपील अदालत के समक्ष अपील करने या अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता देने की राय दी और अंत में अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए आवेदन लेने के बावजूद कई अनुसरणों के बाद इसे 07.06.2010 पर दायर किया गया।
>
> 15. कोई अन्य वैकल्पिक आवेदक नहीं मिलने के कारण उन्हें प्रमाणित प्रति के बिना अपील करने की सलाह दी गई है और

अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है और इसकी अनुमति दी गई है।

जेरॉक्स प्रमाणित प्रति के आवेदन के लिए रसीद की फोटोकॉपी इसके साथ संलग्न की गई है और 'ए' अक्षर से चिह्नित है।

16. कि उक्त परमादेश अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी उपरोक्त कारणों से हुई है जो आवेदकों के नियंत्रण से बाहर थी और पूरी तरह से अनजाने में थी।"

18. इसके बाद, आवेदक ने देरी की माफी के लिए आवेदन पर विचार करते हुए न्यायालय के कर्तव्य के बारे में कहा और उस संदर्भ में, निम्नलिखित रूप में कहाः-

"फिर भी सबूत के सख्त मानक को अपनाने से सार्वजनिक न्यायाधीश की गंभीर विफलता हो सकती है, इसके अलावा अपील दायर करने की प्रक्रिया में देरी के कुशल प्रबंधन से सार्वजनिक शरारत हो सकती है, अपीलकर्ताओं/आवेदकों को उक्त परमादेश अपील को प्राथमिकता देने में लगभग 2449 दिनों की देरी से लाभ नहीं होता है, और न ही यह एक तथ्य है कि यदि इस तरह की गैर-जानबूझकर देरी को माफ नहीं किया जाता है तो रिट याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादी को भारी/पूर्वाग्रह होगा। जानबूझकर देरी नहीं की गई है जैसा कि पूर्वगामी अनुच्छेदों से पता चलता है। इस तरह की गैर-जानबूझकर की गई देरी को माफ करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप तत्काल मामले जैसे गुणकारी मामले हो सकते हैं, जिन्हें बहुत हद तक खारिज कर दिया जाता है और न्यायाधीश का कारण विफल हो जाता है। इसके विपरीत जब देरी को माफ कर दिया जाता है तो तत्काल मामले में

जो सबसे अधिक हो सकता है वह यह है कि पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोष के आधार पर एक कारण तय किया जाएगा।"

19. कथित आधारों का प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिवादी ने यह कहते हुए विरोध किया कि स्कूल के अधिकारियों को दिनांकित आदेश के बारे अन्य बातों के साथ साथ बहुत जानकारी थी क्योंकि यह उनके वकील के साथ-साथ स्कूल के जिला निरीक्षक द्वारा उन्हें सूचित किया गया था। इसके अलावा, प्रबंध समिति द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक वचन दिया गया था। उपरोक्त के अलावा, किसी भी मामले में, 2009 में अस्तित्व में आई नई प्रबंध समिति को आदेश के बारे में पता था, लेकिन उसने तब तक आदेश पर हमला नहीं करने का फैसला किया जब तक कि सचिव और प्रभारी शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश नहीं दिया जाता। यह आगे कहा गया कि जिन आधारों का आग्रह किया गया है, वे इस तरह की भारी देरी की माफी को उचित नहीं ठहराते हैं और पूर्वाग्रह की याचिका बिल्कुल भी मान्य नहीं थी।

20. शपथ पत्र में आग्रह किए गए आधारों और विलंब की माफी के लिए प्रतिवादी द्वारा यहां रखे गए रुख के अवलोकन पर यह है कि वे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के बारे में तब तक नहीं जानते थे जब तक कि उन्हें अवमानना आवेदन की सूचना नहीं मिली और उसके बाद वकील और पक्षों के बीच गलत संचार के कारण कोई कदम नहीं उठाया जा सका और अंततः, रोक हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया और उसके बाद, अपील को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया है कि यदि देरी को माफ नहीं किया जाता है तो सार्वजनिक न्यायाधीश की बड़ी विफलता होगी जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शरारत होगी और यदि वर्तमान जैसे सराहनीय मामले को दहलीज पर फेंक दिया जाता है तो न्यायाधीश का कारण विफल हो जाएगा। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने आवेदन के

पैराग्राफ 14 में किए गए कथनों पर ध्यान दें और उसके बाद, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दें, ओरिएंटल अरोमा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख किया और निम्नानुसार निर्णय लियाः-

> "अब देरी को क्षमा करने के लिए की गई प्रार्थना पर बारीकी से नज़र डालने पर हम पाते हैं कि हालाँकि देरी पर्याप्त है, लेकिन इसे इस तरह से समझाने की कोशिश की गई है, भले ही यह पूर्ण प्रमाण न हो, लेकिन काफी आश्वस्त करने वाला हो।"

21. उपरोक्त को छोड़कर, अधिकांश चर्चा मामले के गुण-दोष से संबंधित है। हमारा मानना है कि उच्च न्यायाधीशालय ने कुछ तथ्यों पर विचार नहीं करके खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है, जैसे कि (क) पूर्ववर्ती प्रबंधन समिति को रिट याचिका का नोटिस दिया गया था; (ख) पूर्ववर्ती समिति रिट अदालत में पेश हुई थी और कार्यवाही और आदेश से अवगत थी; (ग) विद्यालयों के जिला निरीक्षक ने विद्वान एकल न्यायाधीशाधीश के आदेश का पालन करने के लिए प्रबंधन समिति को सूचित किया था; (घ) कि पूर्ववर्ती प्रबंधन समिति ने विद्वान एकल न्यायाधीशाधीश के समक्ष आदेश का पालन करने का बीड़ा उठाया था; (ङ) कि नई प्रबंधन समिति ने पूर्ववर्ती प्रबंधन समिति से कार्यभार संभाला था; (च) शपथ पत्र में कुछ भी संकेत नहीं दिया गया है कि किस परिस्थिति में नई प्रबंधन समिति ने कार्यभार संभालने के बावजूद कार्यभार नहीं संभाला था।

22. इस मोड़ पर, हम यह बताने के लिए बाध्य हैं कि जिन व्यक्तियों को स्कूलों की प्रबंधन समितियों के सदस्यों के रूप में नामित या शामिल किया जाता है या सचिवों के रूप में चुना जाता है, उन्हें जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए और आकस्मिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। यह एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है और जो

कोई भी इस तरह की जिम्मेदारी लेने का इच्छुक है, उसे समय देना होगा और उचित सावधानी और आवश्यक सावधानी के साथ कार्य करना होगा। समिति का सदस्य बनना स्थानीय स्थिति सिंड्रोम नहीं बनना चाहिए। वैधानिक समिति अदालत द्वारा पारित आदेश के प्रति पूरी तरह से उदासीन नहीं रह सकती है और "कुंभकर्ण" की तरह सो नहीं सकती है। प्रबंध समिति की ओर से कार्य करने के लिए चुने गए व्यक्ति कल्पना का सहारा नहीं ले सकते हैं और फीनिक्स की तरह उठ कर अदालत का रुख नहीं कर सकते हैं। ज्ञान की कमी या न्यायाधीश की विफलता के आधार पर लगभग सात साल की देरी की माफी की मांग करते हुए एक आवेदन दायर करते समय न तो अवकाश और न ही आनंद के लिए कोई जगह है। वर्तमान मामले में ज्ञान की कमी की दलील में वास्तव में प्रामाणिकता का अभाव है। उच्च न्यायाधीशालय की खण्ड पीठ न्यायाधीशिक विवेकाधिकार के प्रयोग की अवधारणा के प्रति खुद को जीवित रखने में विफल रही है जो तर्क और न्यायाधीश के नियमों द्वारा शासित है। इसे एन. बालकृष्णन (ऊपर) के निम्नलिखित अंश तक खुद को जीवित रखना चाहिए थाः-

> "सीमा का कानून इस तरह की कानूनी चोट के निवारण के लिए इस तरह के कानूनी उपचार के लिए एक जीवनकाल तय करता है। समय बहुमूल्य है और समय की बर्बादी कभी फिर से नहीं होगी। समय के प्रवाह के दौरान, नए कारण सामने आएंगे जिनसे नए व्यक्तियों को अदालतों का दरवाजा खटखटाकर कानूनी उपचार लेने की आवश्यकता होगी। इसलिए प्रत्येक उपचार के लिए एक जीवनकाल तय किया जाना चाहिए। उपचार शुरू करने के लिए अंतहीन अवधि अंतहीन अनिश्चितता और परिणामी अराजकता का कारण बन सकती है। इस प्रकार सीमा का कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है। यह अधिकतम ब्याज सूची में निहित है (यह सामान्य कल्याण के लिए है

कि एक अवधि मुकदमेबाजी के लिए रखी जाए)। सीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं। वे यह देखने के लिए हैं कि पक्ष विलम्बकारी रणनीति का सहारा न लें, बल्कि तुरंत अपना उपचार लें। विचार यह है कि प्रत्येक कानूनी उपाय को विधायी रूप से निर्धारित अवधि के लिए जीवित रखा जाना चाहिए।"

हमने उसी बात को दर्द के साथ दोहराया है।

23. नतीजतन, अपीलों की अनुमति दी जाती है और खण्ड पीठ द्वारा विलंब को माफ करते हुए पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। इस तरह के विलुप्त होने के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष अपील भी खारिज हो जाएगी। विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि वह 2003 की रिट याचिका संख्या 6124 (डब्ल्यू) का जल्द से जल्द निपटान करे, अधिमानतः, छह महीने की अवधि के भीतर क्योंकि इसमें शामिल याचिकाओं में अधिक समय लगने की संभावना नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आर. पी. अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।